

सात साल बाद नर्सरी बनाने को आइआइटी राजी, बजट की कमी, केंद्र से मांगी धनराशि

कवायद ● परिसर में हरियाली बढ़ाने के लिए दो हेक्टेयर में संस्थान बनाएगा नर्सरी

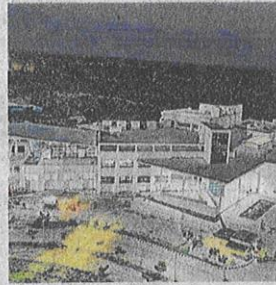
कपिल नीले • इंदौर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) इंदौर के निर्माण को लेकर जो शर्त वन विभाग ने प्रबंधन के सामने रखी थी, उसका अब सात साल बाद संस्थान पालन करने जा रहा है। 40 प्रतिशत जंगल की जमीन पर बने आइआइटी को इस क्षेत्र में हरियाली बढ़ानी है। परिसर में दो हेक्टेयर में नर्सरी बनाकर वन विभाग को सौंपने का रास्ता साफ हो चुका है। आइआइटी ने विभाग को पत्र लिखकर जानकारी दी, लेकिन नर्सरी पर होने वाले खर्च के लिए संस्थान के पास बजट नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार से धनराशि मांगी जा रही है। वैसे यह काम अगले कुछ सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि केंद्र और प्रदेश सरकारें आपस में समन्वय करने में जुटी हैं।

200 हेक्टेयर में फैले आइआइटी का कुछ हिस्सा जंगल की जमीन पर बना है, जो 80 हेक्टेयर बताया जा रहा है। निर्माण के दौरान वन विभाग ने इस हिस्से में हरियाली बढ़ाने की शर्त रखी थी। यहां पौधे लगाने और हरा-भरा रखने के लिए

आठ हजार पौधे तैयार होंगे

दो हेक्टेयर में बनने वाली नर्सरी में आठ हजार पौधे रोपे जाएंगे। यहां दुर्लभ प्रजातियों के पौधे तैयार होंगे। ये काम वन विभाग के जिम्मा आया है। नर्सरी में बीट गार्ड आफिस और रेस्ट हाउस रहेगा। इसका निर्माण भी आइआइटी करेगा। नर्सरी में तैयार पौधे आइआइटी परिसर और आसपास के वनक्षेत्र में रोपे जाएंगे।



नहीं काटा एक भी पेड़

80 हेक्टेयर वनक्षेत्र के 33 प्रतिशत हिस्से में आइआइटी निर्माण कर सकता था, यानी मात्र 26 हेक्टेयर में आने वाले पेड़ काटने की अनुमति थी। बदले में आइआइटी को परिसर में दोगुने पौधे लगाने की शर्त थी। खास

बात यह है कि आइआइटी ने वनक्षेत्र में छेड़छाड़ किए बिना निर्माण कर दिया। अधिकारियों के अनुसार 80 हेक्टेयर में एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। इसके बावजूद आइआइटी को हरियाली बढ़ाने की शर्त पूरी करनी है।

परिसर में नर्सरी बनाकर वन विभाग को देने के लिए आइआइटी राजी हो गया है। फरवरी के पहले सप्ताह में संस्थान ने पत्र लिखा है। काम जल्द शुरू करने के बारे में बताया है। पूरा खर्च संस्थान को उठाना है।

—एके श्रीवास्तव, एसडीओ इंदौर वनमंडल

आइआइटी में नर्सरी बनाई जाएगी। इसके खर्च को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। संस्थान के पास अभी नर्सरी को लेकर बजट नहीं है। वैसे भी निर्माण शिक्षा मंत्रालय ने करवाया है। बजट के लिए केंद्र-प्रदेश सरकारें समन्वय कर रही हैं। जल्द ही राशि आवंटित हो सकती है।

— प्रो. सुनील कुमार, प्रवक्ता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर

प्रोजेक्ट में 2 हेक्टेयर में नर्सरी बनाई जानी थी। प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दी। शुरुआत में आइआइटी ने रुचि कम दिखाई। 2015 में आइआइटी बनकर तैयार हुआ। 2018 में वन विभाग ने नर्सरी बनाने को लेकर आइआइटी को पत्र लिखा। उसके बाद दोनों के अधिकारियों

के बीच बैठकों के कई दौर हुए। खर्च को लेकर आपसी तालमेल नहीं बैठा। उस दौरान नर्सरी पर 60-65 लाख रुपये का खर्च बताया गया। इसमें एक बीट गार्ड कार्यालय भी शामिल है। वर्तमान में इस खर्च में 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। आइआइटी को 70-75

लाख रुपये नर्सरी पर खर्च आने वाला है। फरवरी में आइआइटी नर्सरी बनाकर देने को राजी हुआ है। बजट का अभाव होने से केंद्र सरकार से धनराशि मांगी है। मामले में वन विभाग को भी पत्र लिखा है। अधिकारियों के अनुसार नर्सरी का डिजाइन जल्द बनाकर दिया जाएगा।